रणजीत टाइम्स

इंदौर

बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026

वर्ष 02 | अंक 248 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

'मुकाबले से डरते नहीं'

- मस्क ने स्टारलिंक की लॉन्चिंग में देरी के लिए अंबानी को ठहराया था जिम्मेदार
- रिलायंस ने कहा- भारत में हर कंपनी को करना होगा सरकार के नियमों का पालन
- रिलायंस बोली- मुकाबले से पता चलेगा, ग्राहकों को कौन बेहतर सेवा देता है

मुंबई • एजेंसी

सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'स्टारलिंक' की भारत में एंट्री को लेकर चल रहे विवाद के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि वह कॉम्पिटिशन से नहीं डरता। कंपनी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि असली मुकाबला वही है, जिससे यह पता चले कि सबसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है। कंपनी ने यह बयान एलन मस्क की ओर से लगाए गए उन आरोपों के बाद जारी किया, जिनमें उन्होंने भारतीय टेलिकॉम कंपनियों पर स्टारलिंक का रास्ता रोकने का दावा किया था।

2016
में रिलायंस ने जियो को किया था पेश

53
लाख से अधिक ग्राहक जियो से जुड़े

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि वह भारत के सैटेलाइट संचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, जिसमें एलन मस्क की स्टारलिंक भी शामिल है। साथ ही, कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में काम करने वाली हर कंपनी को कानून के शासन और देश के मौजूदा नियमों का पालन करना होगा।

रिलायंस और भारतीय बाजार को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर, हम तथ्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। हर भारतीय कंपनी की तरह, रिलायंस का विकास भी ऐसे भारत में हुआ है जो निवेश और नवाचार (इनोवेशन) का स्वागत करता है। चाहे वह देश का हो या विदेश का। बशर्ते उससे लोगों के जीवन में सुधार आए।



लॉन्चिंग में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे मस्क

रिलायंस ने कहा कि हमने कभी प्रतिस्पर्धा से परहेज नहीं किया है। हम इसे इस बात की सबसे सटीक परीक्षा मानते हैं कि कौन ग्राहकों को सबसे अच्छी सेवा देता है। 2016 में, जियो भारत के भीड़-भाड़ वाले टेलीकॉम बाजार में एक नए खिलाड़ी के तौर पर उतरा था। महज दस वर्षों में, जियो ने 53 लाख से अधिक ग्राहकों का भरोसा जीता है। भारतीयों को दुनिया का बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध कराया है। जियो समेत हर कंपनी को भारत के लोगों की सेवा करनी होगी और देश के कानूनों व नीतियों का पालन करना होगा। एलन मस्क भारत में स्टारलिंक की लॉन्चिंग में हो रही देरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस देरी के लिए वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जिम्मेदार बता रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हाल ही में मस्क ने अपने एक पोस्ट में मुकेश अंबानी पर तंज कसते हुए उन्हें 'प्राइम मिनिस्टर अंबानी' लिखा था। इस पोस्ट में उन्होंने अंबानी को भारत का रियल बॉस बताया था।

सरकार बोली स्टारलिंक सहित तीन कंपनियों को दिए गए हैं लाइसेंस

'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026' में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने बताया कि देश में तीन सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को लाइसेंस मिल चुके हैं। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि लाइसेंस पाने वाली इन सभी कंपनियों की सिक्योरिटी क्लीयरेंस अभी बाकी है। इसके अलावा सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का प्राइसिंग फ्रेमवर्क भी तय किया जा रहा है। सभी जरूरी शर्तें पूरी होने के बाद ही भारत में ये सेवाएं शुरू हो सकेंगी।

पांच साल के उच्चतम स्तर पर सरकारी स्टॉक

गेहूं के दाम 5% से ज्यादा बढ़े

नई दिल्ली • एजेंसी

भारत सरकार की ओर से 24 अगस्त को गेहूं और इसके उत्पादों (जैसे आटा, मैदा और सूजी) के निर्यात पर चार साल से जारी प्रतिबंध हटाए जाने के बाद गेहूं की कीमतों में 150 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर के करीब चल रही हैं।

24 अगस्त को नई दिल्ली में गेहूं का दाम 2879 रुपए प्रति क्विंटल था, जो 14 अक्तूबर को बढ़कर 3030 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। इस दौरान दिल्ली में गेहूं की कीमत में 151 रुपए प्रति क्विंटल या 5.24 फीसदी की वृद्धि हो चुकी है। गेहूं की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर खुदरा बाजार में आटा, मैदा, सूजी और बिस्कुट-ब्रेड जैसे बेकरी उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा। इससे आम परिवारों के मासिक बजट पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।



सरकार के पास है पर्याप्त स्टॉक | राहत की बात यह है कि सरकार के पास पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। यदि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ती हैं, तो सरकार बाजार में हस्तक्षेप कर सकती है और दाम नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त गेहूं खुले बाजार में बेच सकती है। एफसीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि एक सितंबर तक गेहूं का स्टॉक 479 लाख टन के 5 साल के उच्चतम स्तर पर है।

वित्त मंत्रालय का ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों के 30 दिन के बोनस को मंजूरी

नई दिल्ली • देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को जिसका इंतजार था, उसका ऐलान सरकार ने कर दिया है। केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए एड-हॉक बोनस (दिवाली बोनस) को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर, गुरुवार की शाम को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। इसके तहत पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के कैलकुलेशन के लिए मिनिमम सैलरी की अधिकतम सीमा 7,000 रुपए तय की गई है। इस आधार पर अधिकतम बोनस 6,908 रुपए बनता है।

बोनस के लिए सामान्य पात्रता शर्तों के मुताबिक, कर्मचारी को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने लगातार सेवा पूरी करनी चाहिए। साथ ही, सामान्य नियम के तहत कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है। छह महीने से एक साल तक की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। पात्र सेवा की अवधि की गणना महीनों में की जाएगी और उसे नजदीकी पूर्ण महीने तक माना जाएगा।

यूनियन बैंक का मुनाफा दूसरी तिमाही में 32 प्रतिशत बढ़ा



मुंबई • सरकारी क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। बैंक का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 32 प्रतिशत बढ़कर 5,781 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 4,425 करोड़ रुपए था। सितंबर तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज से आय सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़कर 10,582 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 8,813 करोड़ रुपए थी। बैंक का कंसोलिडेटेड परिचालन से मुनाफा चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में सालाना आधार पर करीब 19 प्रतिशत बढ़कर 8,150 करोड़ रुपए हो गया है।

भारत-यूएस ट्रेड डील का जल्द हो सकता है ऐलान : रुबियो



वाशिंगटन • अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब है। भारत की अपनी यात्रा से पहले उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित समझौते पर अधिकांश काम पूरा हो चुका है। भारत दौरे से पहले रुबियो ने कहा- हम इस समय भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा करने के बहुत करीब हैं। रूसी तेल और गैस के मुद्दे पर रुबियो ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति और कीमतों पर पड़ने वाले असर को देखते हुए अमेरिका को पिछले कुछ महीनों में कई प्रतिबंधों में छूट देनी पड़ी है।

सोना 1.48 लाख रुपए के पार, चांदी में भी मजबूती



नई दिल्ली • वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंकाओं में कमी आने के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। एमसीएक्स पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना वायदा 461 रुपए यानी 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,48,379 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,47,918 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान सोना 581 रुपए यानी 0.4 प्रतिशत उछलकर 1,48,499 रुपए प्रति 10 ग्राम के इंट्रा-डे उच्च स्तर तक पहुंच गया।

कटारिया ट्रेडर्स का भव्य शुभारंभ, मुख्य अतिथि गोपाल गावंडे ने फीता काटकर किया उद्घाटन

प्रतिष्ठान के संचालक निरंजन सिंह सैनी को दी शुभकामनाएं, माँ अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भेंट कर किया सम्मान

इंदौर। व्यापार एवं निर्माण क्षेत्र में एक नई पहल के रूप में कटारिया ट्रेडर्स (Katariya Traders) का आज भव्य शुभारंभ उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक रणजीत टाइम्स के प्रधान संपादक एवं भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गोपाल गावंडे उपस्थित रहे। उन्होंने विधिवत फीता काटकर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया तथा संस्थान के संचालक श्री निरंजन सिंह सैनी को नए व्यावसायिक सफर के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

उद्घाटन समारोह में पुष्पमालाओं, मिठाई वितरण एवं पारंपरिक स्वागत के साथ खुशी का माहौल रहा। इस अवसर पर लोकमाता पुण्यश्लोक माँ अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मान एवं शुभकामनाएं व्यक्त की गईं। स्टोन एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की जरूरतों का एक ही स्थान पर





समाधान प्रतिष्ठान के संचालक श्री निरंजन सिंह सैनी ने बताया कि कटारिया ट्रेडर्स में स्टोन एवं निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के एडहेसिव, केमिकल, एक्सेसरीज एवं संबंधित उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका संस्थान केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े स्तर पर निर्माण कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। संस्थान द्वारा बड़ी बिल्डिंगों के निर्माण कार्य, स्टोन वर्क एवं अन्य कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ठेके भी लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कटारिया ट्रेडर्स के पास विभिन्न निर्माण संबंधी उत्पादों की डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था भी है, जिसके माध्यम से व्यापारियों, ठेकेदारों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े ग्राहकों तक उत्पाद उपलब्ध कराए जाएंगे।

व्यापार के साथ गुणवत्ता और विश्वास को प्राथमिकता इस अवसर पर श्री गोपाल गावंडे ने कहा कि किसी भी व्यवसाय की वास्तविक पहचान उसकी गुणवत्ता, ईमानदारी, ग्राहक सेवा और विश्वास से बनती है। उन्होंने कहा कि नए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की शुरुआत से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलती है और रोजगार एवं विकास के नए अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने संस्थान के संचालक निरंजन सिंह सैनी के उज्ज्वल भविष्य और व्यापार की निरंतर प्रगति की कामना की। कटारिया ट्रेडर्स के संचालक निरंजन सिंह सैनी ने सभी अतिथियों एवं शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता, उचित मूल्य और विश्वसनीय सेवाएं उपलब्ध कराना ही संस्थान की प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम का समापन मिठाई वितरण, बधाइयों और मंगलकामनाओं के साथ हुआ।

डिवीजन स्केटिंग प्रतियोगिता में दून पब्लिक स्कूल, शिवपुरी का शानदार परचम; नन्हें खिलाड़ियों ने जीते कई पदक

ऋषि गोस्वामी

ग्वालियर में हाल ही में आयोजित संभाग स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में दून पब्लिक स्कूल, शिवपुरी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय और पूरे शिवपुरी जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन स्पीड और अनुशासन का परिचय देते हुए कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए।

खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शनः गुरबख्श सिंह भुल्लर (अंडर-11 आयु वर्ग): इन्होंने 'इनलाइन स्केटिंग' (Inline Skating) प्रतियोगिता में अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और कुल दो स्वर्ण (Gold) और एक सिल्वर (Silver) मेडल हासिल किए।

समर हिंडोलियाः इन्होंने अपनी शानदार रेस और संतुलन का प्रदर्शन करते हुए तीन कांस्य (Bronze) पदक अपने नाम किए।



काव्या सिकरवार (बालिका वर्ग): इन्होंने कड़े मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दो कांस्य और एक सिल्वर मेडल प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया।

विद्यार्थियों की इस अपार सफलता पर स्केटिंग कोच अमित गौर ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "सफलता केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में है। मुझे अपने सभी खिलाड़ियों के समर्पण और मेहनत पर गर्व है।"

विद्यालय की डायरेक्टर डॉ. खुशी खान ने सभी विजेता बच्चों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, "डिवीजन स्केटिंग प्रतियोगिता में हमारे विद्यार्थियों की यह उपलब्धि पूरे विद्यालय परिवार के लिए गर्व और हर्ष का विषय है।

बच्चों का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी कड़ी मेहनत और लगन को दर्शाता है। मेरी हार्दिक कामना है कि हमारे सभी विद्यार्थी शिक्षा के साथ-साथ खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊँचाइयाँ छूते रहें और अपने माता-पिता, विद्यालय एवं शिवपुरी का गौरव बढ़ाते रहें।"

इस शानदार उपलब्धि पर स्कूल के समस्त स्टाफ, शिक्षकों और शिवपुरी के गणमान्य नागरिकों ने विजेता खिलाड़ियों और विद्यालय परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। अब ये सभी विद्यार्थी राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में भागीदारी करेंगे।

शिवपुरी में माँ कैला देवी युवा समिति का भव्य आयोजनः परंपरा और उत्साह के साथ हो रही है माता की आराधना

शिवपुरी जिले में इन दिनों शारदीय नवरात्र के अवसर पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। शहर के वार्ड क्रमांक 20 में स्थित माँ कैला देवी युवा समिति द्वारा हर वर्ष की भाँति इस बार भी माता रानी की प्रतिमा को अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ विराजमान किया गया है। समिति से जुड़े परमानंद योगी ने



जानकारी दी कि वे पिछले कई वर्षों से इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। वहीं, समिति के सदस्य रोहित रजक ने बताया कि यह परंपरा उनके बुजुर्गों और पिताओं के समय से चली आ रही है, जिसे युवा पीढ़ी पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रही है। समिति का उद्देश्य किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि माँ की भव्य झाँकी सजाकर उनकी आराधना करना और आपसी प्रेम व भाईचारा बनाए रखना है।

9 दिनों तक होते हैं विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक आयोजन

नवरात्र के इन नौ दिनों के दौरान समिति द्वारा प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की नई गतिविधियों और खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े और महिलाएं तक उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें स्थानीय निवासियों के साथ-साथ चंदा-प्रभारी, कोच और अन्य सभी लोग मिलकर पूरा सहयोग प्रदान करते हैं। माँ कैला देवी युवा समिति का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है, बल्कि यह क्षेत्र के लोगों को एकजुट करने और सामाजिक सौहार्द का एक बेहतरीन उदाहरण भी पेश कर रहा है।

शिवपुरी में नवरात्रि महोत्सव की धूमः 25 वर्षों से लगातार हो रहा है श्रीमद्भागवत कथा और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन

शिवपुरीः में नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति और उल्लास का माहौल है। जगह-जगह माता रानी के जयकारों के साथ धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुरानी शिवपुरी के कुशवाहा मोहल्ला स्थित अथाई युवा समिति द्वारा आयोजित 'श्री कमलेश्वर महादेव नवरात्रि महोत्सव एवं श्रीमद्भागवत सप्ताह' इस बार भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अथाई युवा समिति, पुरानी शिवपुरी के मुख्य कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन पिछले 24-25 वर्षों से अनवरत रूप से किया जा रहा है। समय के साथ इस आयोजन का स्वरूप काफी भव्य हो चुका है, और आज इस समिति के साथ लगभग 250 युवा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, सेवा भाव और राष्ट्रीय एकता की भावना के साथ जुड़े हुए हैं।

मुख्य आकर्षणः श्रीमद्भागवत कथा और 12,000 लोगों का विशाल भंडारा इस महोत्सव के तहत प्रतिदिन कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैंः



श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञः महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएँ, पुरुष और युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और कथा का रसपान कर रहे हैं।

विशाल भंडारा एवं महाप्रसादः आयोजन का मुख्य आकर्षण यहाँ होने वाला विशाल भंडारा है। समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी 10,000 से 12,000 श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई है।

दैनिक धार्मिक अनुष्ठानः प्रतिदिन माता रानी की भव्य झाँकी सजाई जा रही है, साथ ही फूल बंगला, विशेष शस्त्र पूजन, और महाआरती जैसे अनुष्ठान संपन्न कराए जा रहे हैं।

सामाजिक एकता और सनातन संस्कृति का संदेश आयोजन समिति के मुख्य कार्यकर्ता महेश कुशवाह ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारा, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय चेतना और सनातन धर्म के संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। युवा पीढ़ी को धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जोड़कर सकारात्मक दिशा देना इस समिति का प्रमुख ध्येय है। महोत्सव की गरिमा बढ़ाने के लिए शहर के कई प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों और गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी उपस्थिति से आयोजनों को और अधिक उत्साह मिल रहा है। पुरानी शिवपुरी के इस पावन आयोजन से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और आत्मीय वातावरण बना हुआ है।

रणजीत टाइम्स

इस महीने संसद का विशेष सत्र संभव

नई दिल्ली • एजेंसी

संसद का विशेष सत्र इसी महीने के आखिर में बुलाया जा सकता है। सरकार इस सत्र में परिसीमन और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भरोसा है कि इन विधेयकों को लोकसभा से पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या है। इसके साथ ही वह विपक्षी दलों से बातचीत कर समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रही है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हो रहा है, जब विपक्ष मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) सहित कुछ छोटे विपक्षी दलों के संपर्क में भी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार लोकसभा में अपनी संख्या को लेकर आश्वस्त है। इसी भरोसे के साथ वह विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि, विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों से बातचीत भी की जा रही है। सरकार फिलहाल विशेष सत्र की तारीखों और उसके कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटी है।

डीएमके और छोटे विपक्षी दलों से संपर्क में सरकार

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार डीएमके से भी बातचीत कर रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु चुनाव के बाद डीएमके के कांग्रेस से अलग होने और इंडिया गठबंधन से बाहर निकलने के बाद यह संपर्क शुरू हुआ है। इसके अलावा सरकार कुछ छोटे विपक्षी दलों से भी समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि मतदान से पहले संख्या मजबूत करना सरकार की रणनीति का अहम हिस्सा है।



मानसून सत्रावसान नहीं, विशेष बैठक बुलाने का रास्ता खुला

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान अभी नहीं हुआ है। यानी सदन की बैठकें भले ही खत्म हो गई हों, लेकिन सत्र को आधिकारिक रूप से बंद नहीं किया गया है। इसी वजह से सरकार के लिए इसी सत्र के तहत विशेष बैठक बुलाने का रास्ता खुला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, विशेष बैठक बुलाने से पहले करीब एक सप्ताह का नोटिस दिया जा सकता है। हालांकि, सत्र की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है।

बजट सत्र के दौरान अप्रैल में लोकसभा में गिर गया था विधेयक

सरकार की यह तैयारी ऐसे समय हो रही है, जब कुछ महीने पहले उसे संसद में झटका लगा था। बजट सत्र के दौरान 17 अप्रैल को परिसीमन और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। विधेयक जरूरी समर्थन हासिल करने में नाकाम रहा था। अब सरकार इसी मुद्दे पर दोबारा प्रयास करने की तैयारी में है। विशेष सत्र बुलाने का मकसद इन प्रस्तावों को फिर से संसद के सामने लाना और उनके लिए जरूरी समर्थन जुटाना बताया जा रहा है।

खरगे ने मोदी को लिखा पत्र, सर्वदलीय बैठक बुलाएं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम नरेंद्र मोदी से परिसीमन बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव संसद में रखने से पहले सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए। पत्र में खरगे ने चेतावनी दी कि सरकार को व्यापक संविधान संशोधन बिल को फिर जबरन पास कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खरगे ने मानसून सत्र समापन नहीं होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा 13 अगस्त को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 64 दिन बाद भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्रावसान नहीं हुआ है।

26-27 अक्टूबर के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तय होगी तारीख

विशेष सत्र की तारीख तय करते समय 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच के कार्यक्रम को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह कार्यक्रम 26 और 27 अक्टूबर को संविधान सदन में आयोजित होना है। ऐसे में सरकार इसी कार्यक्रम के आसपास की तारीखों को ध्यान में रखकर विशेष बैठक का कार्यक्रम तय कर सकती है। दूसरी ओर, विपक्ष एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। ऐसे राजनीतिक माहौल में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने की सरकार की तैयारी पर सभी की नजरें रहेंगी। हालांकि, विशेष सत्र बुलाने और विधेयकों को पेश करने को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।

एक नजर

मुंबई में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से मिलेंगे जयशंकर

नई दिल्ली • विदेश मंत्री एस. जयशंकर 20 अक्टूबर को मुंबई में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसकी जानकारी दी। जयशंकर इस दौरान अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान 19 और 20 अक्टूबर को मुंबई के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर उनकी मेजबानी करेंगे।

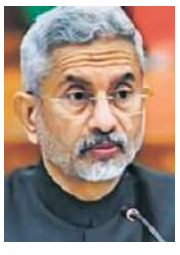

लद्दाख को सांकू के रूप में मिला एक और नया जिला



लेह • लद्दाख को एक और नया जिला मिल गया है। नए जिले के ऐलान के साथ ही लद्दाख में अब कुल 8 जिले हो गए हैं। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने शुक्रवार को 'सांकू' को एक नए जिले के रूप में बनाने की अधिसूचना जारी की है। इस नए जिले का मुख्यालय सांकू में ही बनाया गया है। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नया जिला 'जम्मू और कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम, 1996 की धारा 5 के तहत, 16 अक्टूबर 2026 की S.O. 284 के जरिए बनाया गया है। जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के समय लद्दाख में 2 जिले थे।

केंद्र सरकार दो हफ्ते में जारी करेगी नए नियम

यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से मिलेगी राहत

नई दिल्ली • एजेंसी

यात्रियों को महंगे फ्लाइट टिकटों से जल्द ही राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने एयरलाइंस के मनमाने किराए को कंट्रोल करने के लिए नए नियमों को फाइनल कर लिया है। सरकार दो हफ्ते में इन नए नियमों को जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि जारी नियमों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इस फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर भी दिखा।

सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट एयरलाइंस की ओर से वसूले जाने वाले मनमाने किराए को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस अपारेश सिंह की बेंच को नए नियमों की स्थिति बताई। अगले दो हफ्ते में नए पब्लिश होने वाले नियमों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि त्योहारों, पीक सीजन या इमरजेंसी के समय एयरलाइंस किराए में कितना इजाफा कर सकेंगी। 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पब्लिश नियमों की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद देश में हवाई सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों को मनमाने किराए से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।



भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी की कई उड़ानें की रद्द | सऊदी अरब में सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय कंपनियों एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुक्रवार को सऊदी के लिए अपनी उड़ान सेवाएं 20 अक्टूबर तक निलंबित करने की घोषणा की। एयरलाइंस ने रियाद, जेद्दा और दम्माम सहित सऊदी अरब के प्रमुख शहरों के लिए उड़ान सेवाएं अलग-अलग अवधि तक निलंबित की है। कुछ एयरलाइंस ने मदीना के लिए भी उड़ानें रद्द की हैं।

दिपके के बाद राहुल पर भड़कीं अमेरिकी गायिका मैरी

देश के युवा गलत रास्ते पर न जाएं, कांग्रेस और कॉकरोच पार्टी सिर्फ शोर मचा रही

नई दिल्ली • एजेंसी

भारत में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर अब अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन भी बयानबाजी कर रही हैं। मिलबेन ने दावा किया कि इन प्रदर्शनों के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलती है। उन्होंने कहा कि कि बार-बार यही सवाल आ रहा है कि आखिर इन लोगों की फंडिंग कौन कर रहा है।

उन्होंने दावा किया, इसके पीछे भी वही लोग हैं जो कि कई ऐसे प्रदर्शनों को फंड देते हैं। खास तौर पर जब कोई दक्षिणपंथी नेता सत्ता में होता है तो ये लोग फंड करते हैं और उनका नाम है जॉर्ज सोरोस। वहीं शुक्रवार को एक और वीडियो पोस्ट करते हुए मिलबेन ने राहुल गांधी पर हमला किया। मिलबेन ने दावा किया कि दुनियाभर में जॉर्ज सोरोस अराजकतावादी प्रदर्शनों को फंड करते हैं। उन्होंने कहा कि अभिजीत दिपके ने खुद यह बात कबूली थी कि जॉर्ज सोरोस उनकी मदद करते हैं। उन्होंने यह बयान बुधवार को दिया था।

मिलबेन ने अभिजीत दिपके को सलाह दी कि वह प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बात करें और अपनी ऊर्जा को देश की प्रगति में लगाएं। मिलबेन ने कहा कि देश के युवाओं को गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लेते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी केवल शोर मचा रही है। इसमें कोई भी समाधान नहीं है। आवाज ऐसी होनी चाहिए जो कि एकता का संदेश दे और लोगों को साथ लाए।



महाराष्ट्र में सालभर पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध

मुंबई • बॉम्बे हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने को लेकर सख्त आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे फोड़ने पर अब सालभर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और अन्य सभी प्रमुख त्योहारों के दौरान पूरे महाराष्ट्र राज्य में अनिवार्य रूप से लागू होगा। त्योहारों के जुलूसों के दौरान होने वाले बेकाबू शोर और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्देश दिया गया है। जस्टिस गिरीश एस. कुलकर्णी और जस्टिस नीला के. गोकले की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक नागरिक हालात की जरूरत को नहीं समझेंगे और शहरों में रहने के लंबे समय के खतरों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हालात बिगड़ते रहेंगे। ऐसे शहर गैस चैंबर में बदल सकते हैं। बेंच ने यह भी साफ किया कि समस्या नए कानूनों की कमी नहीं, बल्कि मौजूदा कानूनों का कड़ाई से पालन न होना है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों के अधिकार सबसे महत्वपूर्ण हैं और हम सभी संविधान से बंधे हैं। यह आदेश मुख्य रूप से 22 सितंबर को गणेशोत्सव के दौरान दिए गए पिछले निर्देशों का दायरा बढ़ाते हुए आया है, जिसे अब पूरे साल के लिए प्रभावी कर दिया गया है।

संपादकीय

विनिवेश की नीति और आर्थिक असमानता

भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ 1991 में शुरू हुई विनिवेश की प्रक्रिया ने देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। भुगतान संतुलन के गंभीर संकट और विदेशी मुद्रा की कमी ने सरकार को नए आर्थिक विकल्प अपनाने के लिए विवश किया। इसके बाद सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति लगातार आगे बढ़ती रही। नेहरू के दौर में अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना, कृषि में निवेश बढ़ाना और आर्थिक असमानता घटाना था। इस व्यवस्था ने सीमित संसाधनों वाले देश में औद्योगिक आधार और मध्यम वर्ग के विस्तार में योगदान दिया। हालांकि, धीमी विकास दर और सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता पर सवाल भी उठते रहे। उदारीकरण ने प्रतिस्पर्धा, विदेशी निवेश और उपभोक्ताओं के लिए नए विकल्पों के रास्ते खोले, लेकिन इसके साथ आय और संपत्ति की असमानता बढ़ने की चिंता भी गहरी हुई।

विनिवेश की शुरुआत कांग्रेस सरकार के समय हुई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसे अधिक संस्थागत रूप मिला। अरुण शौरी को विनिवेश मंत्री बनाया गया और सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के लक्ष्य बजट का हिस्सा बनने लगे। इसके बाद विभिन्न सरकारों ने इसी आर्थिक दिशा को आगे बढ़ाया। इससे स्पष्ट है कि विनिवेश अब किसी एक दल की नीति नहीं, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बन चुका है। आज सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी निजी कंपनियों को बेचने का सवाल फिर चर्चा में है। आईडीबीआई बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी बेचने जैसे फैसले इसी नीति की अगली कड़ी हैं। ऐसे निर्णयों का मूल्यांकन केवल सरकार को मिलने वाली रकम या निवेश के आकार से नहीं होना चाहिए। यह भी देखना जरूरी है कि बिक्री की शर्तें पारदर्शी हैं या नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों का उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं और आम नागरिकों के हित कितने सुरक्षित हैं। आर्थिक विकास के लिए निजी निवेश और प्रतिस्पर्धा आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को केवल लाभ-हानि के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। बैंकिंग, कृषि और बुनियादी सेवाओं में उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।

नवी पिल्लै को मिला नोबेल हाथ मलते रह गए ट्रंप

9 अक्टूबर 2026 को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका की वरिष्ठ न्यायविद् और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लै को इस सम्मान के लिए चुना गया। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कई अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को समाप्त कराने का दावा करते रहे हैं और नोबेल शांति पुरस्कार पाने की इच्छा भी जता चुके हैं, एक बार फिर निराश रह गए। नवी पिल्लै का पूरा जीवन रंगभेद के विरोध, मानवाधिकारों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय कानून को मजबूत करने के प्रयासों से जुड़ा रहा है। 1941 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में तमिल भारतीय मूल के परिवार में जन्मीं पिल्लै ने रंगभेद के दौर में वंचितों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों की कानूनी लड़ाई लड़ी।

उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनीं। उनकी अंतरराष्ट्रीय पहचान रवांडा नरसंहार से जुड़े मुकदमों में न्यायिक योगदान और 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में किए गए कार्यों से बनी। रवांडा के अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण में उनके योगदान ने नरसंहार और यौन हिंसा जैसे गंभीर अपराधों की जवाबदेही तय करने में अहम भूमिका निभाई। गाजा और इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भी पिल्लै की भूमिका चर्चा में रही। 2021 से 2025 तक उन्होंने इस क्षेत्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र जांच आयोग की अध्यक्षता की। आयोग ने 2025 में गाजा में नरसंहार के निष्कर्ष दिए। इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मतभेदों के बावजूद, पिल्लै का कार्य मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की जवाबदेही से जुड़ा रहा। सवाल है कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? संघर्षों में मध्यस्थता के उनके दावों और समझौतों के प्रयासों का मूल्यांकन उनके वास्तविक परिणामों के आधार पर होना चाहिए। किसी नेता की इच्छा या उसका राजनीतिक प्रभाव अपने आप पुरस्कार की पात्रता तय नहीं करता। शांति के लिए किए गए प्रयासों की स्वतंत्र और व्यापक समीक्षा आवश्यक है। उसे टिकाऊ बनाने के लिए न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा और युद्ध अपराधों की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।

सहजयोग के माध्यम से जीवन में पूर्णता लाए

योग हमारे देश में एक प्राचीन जीवन विद्या रही है, लेकिन उसे आधुनिक काल में लोगों ने मात्र एक शारीरिक विधि के रूप में सीमित कर दिया है। वास्तव में योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है जिससे मनुष्य अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करे, बल्कि एक ऐसा प्रयास भी है जिससे जीवन में शुभता और दिव्यता की प्राप्ति हो । लोग केवल शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शान्ति की खोज करते हैं, लेकिन वह खोज भौतिक व्यवस्थाओं से जुड़ी रहती है। अगर भौतिक व्यवस्था ठीक है तो स्वास्थ्य और शान्ति के लिये अनुकूल है, और हम भौतिक स्तर पर ही अपने आप को प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि जीवन में संघर्ष ही रहते हैं। हमारे मनीषियों ने योग का आविष्कार मनुष्य के जीवन को पूर्णरूप से सुधारने के लिये किया था, केवल रोग को दूर करने के लिये नहीं। जीवन को पूर्णरूप से सुधारने का मतलब होता है अपनी शारीरिक ऊर्जाओं को, प्राणों को संतुलित रखना, मन को व्यवस्थित रखना, मन के विकारों को अपने से दूर रखने का प्रयास करना।



मानसिक विकार हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य-ये छः चीजें मानसिक विकार हैं। जब शरीर रोगग्रस्त होता है तो हम चिकित्सक के पास चले जाते हैं और रोग को दूर करने के लिये दवाई मिल जाती है। मानसिक व्यथा होती है तो हम किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं या फिर किसी साधु-महात्मा के पास जाते हैं इस कामना के साथ कि संभवतः हमें समाधान मिल जायेगा। बहुत स्थानों में समाधान मिलता है, बहुत जगहों में नहीं भी मिलता है, लेकिन जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण केवल शारीरिक और मानसिक सुख से जुड़ा रहता है। कई आत्मसाक्षात्कारी संतों ने बताया है कि मनुष्य का जीवन केवल शरीर और मन के सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है पूर्णता को प्राप्त करना। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते- हमारे जीवन की यात्रा जो पूर्ण से आरम्भ हुई है उसका अन्त भी पूर्णता में ही होना है। इसी पूर्णता सहजयोग के माध्यम से होती है, सहजयोग संस्थापिका परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी साधको को अपनी अमृतवाणी में बताती है कि, मानव अपनी क्रमागत उन्नति के साथ आगे तो बढ़ रहा है, पर उसका सरोकार उसके जीवन देने वाले उस परमात्मा से दूर गया। उसकी पूरी प्राथमिकता अपने खाना, परिवार प्रयोजन और उसकी आवश्यकता तक रह गयी है। परंतु अब वक्त बदल गया है। अब सभी को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए जो पूर्ण रूप से सत्य है। इस सत्य के लिए, हमें अपना आत्मसाक्षात्कार लेना होगा, जो एक गुरु की उपस्थिति में ही पूर्ण होता है। इसलिए इस आत्मसाक्षात्कार को जानना भी मनुष्य की प्रवृत्ति में आना चाहिए । जो जीवन की समस्याओं का पूर्ण समाधान करता है। सहजयोग ध्यान द्वारा आत्मा को पाने की ऐसी पद्धति है जिसमें सहजता से निःशुल्क आत्मसाक्षात्कार प्राप्त होता है। कुंडलिनी जागरण द्वारा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करने के हेतु टोल फ्री नंबर 18002700800 या sahajayoga.org.in संपर्क कर सकते हैं।

शिवपुरी की यातायात व्यवस्था बेपटरी: चौक-चौराहों पर बंद पड़े ग्रीन-रे सिग्नल, भगवान भरोसे चल रहा ट्रैफिक और मस्ती में मस्त जवान

ऋषि गोस्वामी

शिवपुरीः जिले में यातायात व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह से चरमरा गई है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर लगे आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल (ग्रीन और रेड लाइट) पिछले कई सालों से बंद पड़े हैं, जिसके कारण शहरवासियों को रोजाना भीषण जाम और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि चौराहों पर यातायात के जवान तैनात होने के बावजूद अपनी ही मस्ती में व्यस्त नजर आते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

सालों से शोपीस बने हैं ट्रैफिक सिग्नल

शहर के व्यस्ततम चौराहों पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने और नियमों का पालन कराने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। लेकिन देखरेख के अभाव और तकनीकी खराबी के चलते ये सिग्नल लंबे समय से बंद पड़े हैं। स्थिति यह है कि वाहन चालक बिना किसी नियम के अपनी मर्जी से वाहन निकालते हैं, जिससे आए दिन चौराहे



पर अफरा-तफरी का माहौल रहता है।

चौराहों पर तैनात जवानों की उदासीनता

एक तरफ जहां सिग्नल बंद होने के कारण जाम की स्थिति विकराल होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चौराहों पर खड़े यातायात पुलिस के जवान अपनी ड्यूटियों के प्रति लापरवाह दिखाई देते हैं। जाम खुलवाने या यातायात को नियंत्रित करने के बजाय कई जवान या तो मोबाइल में व्यस्त नजर आते हैं या अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आम जनता का आरोप है कि यदि जवान थोड़ा सा भी सक्रिय हो जाएं, तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है।

जनता में बढ़ रहा आक्रोश

रोजाना जाम में फंसने वाले स्थानीय नागरिकों और राहगीरों में ट्रैफिक विभाग की इस लचर कार्यप्रणाली को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि प्रशासन और यातायात विभाग शहर की इस गंभीर समस्या से पूरी तरह आंखें मूंदकर बैठा है। जब तक सिग्नल सुचारू नहीं किए जाते और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक शिवपुरी की सड़कों पर ट्रैफिक का यह हाल यूं ही बना रहेगा।

शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने 'अपना घर गौशाला' में 10 लाख की लागत से बने नवीन शेड का किया लोकार्पण, कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद

ऋषि गोस्वामी

शिवपुरी। शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने 'अपना घर गौशाला' पहुँचकर विधायक निधि एवं जनसहयोग के संयुक्त प्रयासों से 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन शेड का विधिवत लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के तहत कन्या पूजन में सहभागिता की और कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गौ-सेवा को समाज का सबसे बड़ा धर्म बताते हुए विधायक देवेंद्र जैन ने कहा कि "गौ-सेवा ही वास्तव में नारायण सेवा है।" उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है और गौ-वंश की रक्षा तथा उनकी बेहतर देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक निधि से निर्मित यह नया शेड गौ-वंश को मौसम के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके रख-रखाव को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक देवेंद्र जैन ने गौशाला परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और गौ-सेवा के इस पावन कार्य में



निरंतर समर्पित 'अपना घर गौशाला' परिवार के सभी सदस्यों एवं सेवाभावी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी तथा उनके प्रयासों की सराहना करते हुए साधुवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि और गौ-भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

विधायक कैलाश कुशवाह ने पोहरी विधानसभा के ग्राम परिच्छा की करंट पीड़ित आदिवासी बहनों से की मुलाकात, अस्पताल पहुंचकर बंधाया ढांढस

ऋषि गोस्वामी

शिवपुरीः पोहरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कैलाश कुशवाह ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शिवपुरी जिला चिकित्सालय का औचक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम परिच्छा में करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुईं आदिवासी बहनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली। अस्पताल पहुँचकर विधायक कुशवाह ने सीधे घायलों के परिजनों से बातचीत की



और उन्हें हरसंभव सहायता व सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि इस कठिन समय में वे और पूरा प्रशासन उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। चिकित्सकों से की विशेष चर्चा, दिए बेहतर इलाज के निर्देश घायलों के बेहतर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए विधायक ने जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉ. आर. पी. सिंह और न्यूरोसर्जन डॉ. दिनेश गोयल से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने चिकित्सकों से आग्रह किया कि घायल बहनों के उपचार में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए और उन्हें तत्काल प्रभाव से उच्चतम एवं समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

"क्षेत्र की जनता का सुख-दुख मेरा अपना"

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए विधायक कैलाश कुशवाह ने कहा कि क्षेत्र की जनता का सुख-दुख उनका अपना सुख-दुख है। हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ा रहना उनका नैतिक दायित्व और संकल्प है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि सभी घायल बहनें जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच सकुशल लौटें। इस मानवीय पहल पर स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने विधायक कैलाश कुशवाह के प्रति आभार व्यक्त किया है।

दशहरा पर्व पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन

धर्मेन्द्र गुप्ता

जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक तथा कलेक्टर व एसपी ने सहभागिता निभाई विदिशा। आज विदिशा पुलिस लाइन में दशहरा पर्व पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गीता कैलाश रघुवंशी, विधायक श्री मुकेश टण्डन, कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी, वन मण्डलाधिकारी श्री हेमंत यादव अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने सहभागिता निभाई।



विधि विधान पूजन कार्यक्रम के उपरांत पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के शस्त्रों को रखा गया था।

हवन में आहूतियां दी जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, कलेक्टर व एसपी सहित अन्य के द्वारा हवन में शामिल होकर आहुतियां दी हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, कॉ-आपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर शर्मा, ग्यारसपुर जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री छत्रपाल शर्मा, समेत अन्य जनप्रतिनिधि अन्य जनप्रतिनिधिगण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी, समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी - कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी मौजूद रहे।

कंचनपुर में स्वास्थ्य सेवा की सराहनीय पहल, डिटॉक्स

हीलिंग सेंटर में 200 से अधिक लोगों को लाभ मिलने का दावा

निःशुल्क बुनियादी जांच, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने का प्रयास

साहिल खान

शहडोल। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कंचनपुर स्थित डिटॉक्स हीलिंग सेंटर एवं जय मां शारदा आयुर्वेदिक केंद्र की पहल सराहनीय है। 20 अगस्त को शुरू हुए इस सेंटर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, योग और विभिन्न थेरेपी की सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सेंटर से जुड़े डॉ. भवानी प्रसाद मिश्रा और डॉ. एस.पी. मिश्रा के अनुसार, अब तक 200 से अधिक लोग यहां की सुविधाओं का लाभ ले चुके हैं। सेंटर की खास बात यह है कि यहां बीएमआई सहित कुछ बुनियादी जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना लोगों को



अपनी सेहत के प्रति जागरूक करना है। यहां मोटापा, डायबिटीज, माइग्रेन, रीढ़ की समस्याओं, शरीर में दर्द और रक्त संचार संबंधी परेशानियों को लेकर आने वाले लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा, योग और बेहतर जीवनशैली के बारे में जानकारी दी जाती है।

डॉ. भवानी प्रसाद मिश्रा और डॉ. एस.पी. मिश्रा के मार्गदर्शन में सेंटर में स्वास्थ्य जागरूकता के साथ रोजगार और व्यापार संबंधी प्रशिक्षण के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नियमित योग, संतुलित खानपान और अनुशासित दिनचर्या के महत्व को समझाकर लोगों को स्वस्थ जीवन की दिशा में प्रेरित करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। आम लोगों तक बुनियादी जांच और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है।

पताः डिटॉक्स हीलिंग सेंटर एवं जय मां शारदा आयुर्वेदिक केंद्र, दावत रेस्टोरेंट के पास, NH-43, कंचनपुर, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश।

विजयादशमी पर पुलिस लाइन विदिशा में

विधिवत संपन्न हुआ परंपरागत शस्त्र पूजन

धर्मेन्द्र गुप्ता

दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी के पावन अवसर पर पुलिस लाइन विदिशा में परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम विधिवत आयोजित किया गया। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री मुकेश टंडन, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता रघुवंशी, जिला कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता, वनमंडलाधिकारी श्री हेमंत यादव, पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी के द्वारा विधि-विधान से शस्त्रों का पूजन-अर्चन किया गया। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक श्री रोहित काशवानी द्वारा पुलिस वाहनों का भी पूजन कर परंपरा का निर्वहन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री अतुल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक महिला अपराध शाखा श्री सुरेंद्र सिंह, रक्षित निरीक्षक श्री नीरज सिकरवार सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। इसी क्रम में विजयादशमी



के पावन अवसर पर जिले के विभिन्न अनुभागों में भी परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम विधिवत आयोजित किए गए। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने सहभागिता की तथा परंपरानुसार शस्त्रों का पूजन-अर्चन किया गया।

वोट चोरी के खिलाफ मंडेली में कांग्रेस की पदयात्रा

मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन कर भाजपा के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान के अनुच्छेद 326 का किया पाठ, लोकतंत्र की रक्षा का लिया संकल्प

छुरा/मंडेली। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, छुरा के तत्वावधान में सोमवार को ग्राम मंडेली में कथित वोट चोरी के विरोध में पदयात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम की शुरुआत ग्राम पंचायत के सामने स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके पश्चात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, जो वयस्क मताधिकार से संबंधित है, का पाठ किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालते हुए



लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया। पदयात्रा के मुख्य चौराहे पर पहुंचने के बाद भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वोट चोरी के मुद्दे पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट सबसे बड़ी ताकत है और मताधिकार की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता बनाए रखना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पार्टी के निर्देशानुसार यह विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महेश्वरी शाह, जिला महिला कांग्रेस कमेटी गरियाबंद की जिलाध्यक्ष मंजू ध्रुव, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष अब्दुल समद खान, वरिष्ठ कांग्रेसी भानु वर्मा एवं , अवध मरकाम जी, बालमुकुंद चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री हरीश यादव, नीलकंठ ठाकुर मंडल अध्यक्ष छुरा, शांतनु देवांगन पार्षद,सचिव रमेश चंद्राकर, मंडेली मंडल अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर, गोल्डन यादव, युवा नेता मोनू दीक्षित, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रितेश दिक्षित, एनएसयूआई अध्यक्ष विकास दुबे, अल्ताफ खान, वीरेंद्र निर्मलकर, लक्ष्मी ठाकुर, रेवा राम ओगरे, गणेशी बाई, बुधाबाई, ललिता बाई, रजनी, भीखम ध्रुव, देवसिंग, खिलेंद्र, गुलशन, लोचन धुर्वा एवं भागेश्वर ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम मंडेली में आयोजित इस पदयात्रा और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मताधिकार की सुरक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया।

1851 मनोकामना ज्योत के साथ मां शीतला मंदिर का जंवारा विसर्जन संपन्न

अमेरिका और पाकिस्तान तक फैली मां शीतला के भक्तों की आस्था, विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं ने भी प्रज्वलित कराए मनोकामना ज्योत कलश

विसर्जन शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब, बाजे-गाजे और जसगीतों के बीच नगर भ्रमण के बाद राजा तालाब में हुआ जंवारा विसर्जन

छुरा। नगर के प्रमुख आस्था केंद्र मां शीतला मंदिर में क्वांर नवरात्र पर्व के समापन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के वातावरण में भव्य जंवारा विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हुआ। नौ दिनों तक मां शीतला की आराधना, पूजा-अर्चना और मनोकामना ज्योति की अखंड आस्था से आलोकित मंदिर परिसर में विसर्जन के दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस वर्ष मंदिर में कुल 1851 मनोकामना ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए थे। मां शीतला के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छुरा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तथा विदेशों में रहने वाले भक्तों ने भी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की कामना के साथ ज्योत प्रज्वलित कराए। इनमें अमेरिका और पाकिस्तान में रहने वाले श्रद्धालुओं के नाम भी शामिल रहे। इससे मां शीतला मंदिर की धार्मिक महत्ता और श्रद्धालुओं के बीच इसकी व्यापक आस्था का परिचय मिलता है।

1851 मनोकामना ज्योत से जगमगाया मंदिर परिसर

क्वांर नवरात्र के दौरान मां शीतला मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही।



मनोकामना ज्योति कलशों के प्रज्वलन के साथ मंदिर परिसर में नौ दिनों तक भक्तिमय वातावरण बना रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से माता की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य, शांति और खुशहाली की कामना की। नवरात्र के अंतिम चरण में मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। 1851 मनोकामना ज्योत कलशों के माध्यम से श्रद्धालुओं ने अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त की। स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों और विदेशों में रहने वाले भक्तों ने भी मां शीतला के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित की।

जसगीत की साथ निकला भव्य जंवारा डोला

नवरात्र पर्व के समापन पर मंदिर में विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना की गई। धार्मिक अनुष्ठानों के पश्चात मां शीतला के जंवारे का डोला निकाला गया। बाजे-गाजे, पारंपरिक धुनों और जसगीतों के बीच निकली शोभायात्रा में श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। शोभायात्रा के आगे बढ़ने के साथ ही पूरा वातावरण



भक्तिमय हो गया। माता के जयकारों और जसगीतों से नगर की गलियां गूंज उठीं। श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धाभाव के साथ जंवारा डोला में सहभागिता निभाई।

सदर बाजार से राजा तालाब तक हुआ नगर भ्रमण

मां शीतला मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई जंवारा विसर्जन शोभायात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। शोभायात्रा सदर बाजार, बस स्टैंड, बजरंग चौक, आमापारा, मस्जिद पारा और मामूली पारा सहित विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ी। नगर भ्रमण के दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने जंवारा डोला का स्वागत किया। कई स्थानों पर आरती उतारी गई तथा पुष्पवर्षा कर माता के प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। घरों और दुकानों के सामने श्रद्धालु दर्शन के लिए खड़े रहे। महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने धार्मिक उत्साह के साथ शोभायात्रा में भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान नगर का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय नजर आया। मां शीतला के जयकारों के साथ श्रद्धालु जंवारे के दर्शन करते रहे। पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप निकाली गई इस शोभायात्रा ने नवरात्र पर्व की आध्यात्मिक गरिमा को और अधिक विशेष बना दिया।

विसर्जन में उमड़ा जनसैलाब, राजा तालाब में संपन्न हुई परंपरा

जंवारा विसर्जन शोभायात्रा में बड़ी संख्या में नगरवासियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं की सहभागिता रही। शोभायात्रा के मार्गों पर भक्तों की भीड़ दिखाई दी। माता के प्रति श्रद्धा और उत्साह के बीच श्रद्धालु विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हुए। नगर भ्रमण पूर्ण होने के पश्चात परंपरागत रीति-रिवाजों के अनुसार राजा तालाब में जंवारे का विसर्जन किया गया। इस दौरान मां शीतला से क्षेत्र की सुख-शांति, समृद्धि, खुशहाली और जनकल्याण की कामना की गई। जंवारा विसर्जन के साथ ही क्वांर नवरात्र का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। नौ दिनों तक चली पूजा-अर्चना और मनोकामना ज्योति की साधना के समापन पर श्रद्धालुओं ने मां शीतला के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। मंदिर में संपन्न हुआ यह आयोजन छुरा नगर की धार्मिक परंपरा, सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक बना। 1851 मनोकामना ज्योत कलशों के प्रज्वलन और भव्य विसर्जन शोभायात्रा ने एक बार फिर मां शीतला मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था को प्रदर्शित किया।

दशहरा एवं प्रतिमा विसर्जन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी विदिशा ने की पुलिस बल की ब्रीफिंग

धर्मेन्द्र गुप्ता

ड्यूटी हेतु फोर्स को किया रवाना दशहरा पर्व, रावण दहन, चल समारोह एवं प्रतिमा विसर्जन को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी ने पुलिस बल की ब्रीफिंग लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।



विदिशा। इस दौरान सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता और मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के उपरांत पुलिस बल को निर्धारित ड्यूटी स्थलों के लिए रवाना किया गया।

इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी सहित समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

थाना आनंदपुर पुलिस ने विद्युत तार चोरी का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, 40,700 का मशरूका बरामद

धर्मेन्द्रगुप्ता

विदिशा पुलिस द्वारा जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना आनंदपुर पुलिस ने विद्युत लाइन से तार चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 40,700 कीमत का मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

फरियादी जितेन्द्र पिता परमप्रकाश रघुवंशी निवासी ग्राम परवरिया द्वारा विद्युत लाइन से तार चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दिनांक 17-18 जुलाई 2026 की दरमियानी रात परवरिया से आनंदपुर लाइन के विद्युत तार तथा दिनांक 24 जून, 04 जुलाई एवं 13 जुलाई 2026 की रातों में विद्युत विभाग की लाइनों के खंभों से तार काटकर चोरी किए जाने के संबंध में थाना आनंदपुर में अपराध क्रमांक 142/26 एवं 189/26, धारा 136 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।पुलिस अधीक्षक विदिशा श्री रोहित काशवानी द्वारा चोरी के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं चोरी गए मशरूका की बरामदगी के निर्देश दिए गए। निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका तिवारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) लटेरी श्री अमरेश बोहरे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आनंदपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल से प्राप्त भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच करते हुए मुखबिर सूचना पर दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को लटेरी बस स्टैंड के पास से संदेही अनीस खां को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की।

राहुल गांधी खेल रहे देश विरोध का खतरनाक खेल



डॉ. मयंक चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन हमेशा जनता के मतों से तय होता है। परंतु, राहुल गांधी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग देश की चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लांछित करने के लिए किया जाना चिंताजनक है। उनके बयानों में यह राग आलापा गया कि पश्चिमी देश भारत में 'लोकतंत्र की पुनर्स्थापना' के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ये अपील परोक्ष रूप से विदेशी ताकतों को भारत के मामलों में हस्तक्षेप करने का आमंत्रण देने जैसी है।

पिछले कुछ समय से देश में राजनीति का ऐसा विकृत स्वरूप उभर रहा है, जो देश की संप्रभुता के लिए गंभीर चेतावनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब घरेलू राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देश की सीमाओं को लांघकर विदेशी ताकतों, अंतरराष्ट्रीय कॉर्पोरेट्स और वैश्विक संस्थाओं की दहलीज पर समर्थन मांगने लगें तो वह लोकतंत्र को खोखला करती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर जाकर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर दिए गए बयान, एलन मस्क जैसे दंभी विदेशी अरबपतियों की भारत-विरोधी झुंझलाहट और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय जैसी संस्थाओं का पक्षपातपूर्ण रवैया, वस्तुतः यह सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं लगते। एक के बाद एक चुनावों में पराजय झेलने के बाद घरेलू राजनीति में अस्थिरता पैदा करने और चुनी हुई मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ जो परोक्ष जुगलबंदी दिखाई दे रही है, वह देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल को खुला निमंत्रण है।

भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन हमेशा जनता के मतों से तय होता है। परंतु, विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों का उपयोग देश की चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लांछित करने के लिए किया जाना अत्यंत चिंताजनक है। उनके बयानों में बार-बार यह राग आलापा गया कि पश्चिमी देश भारत में 'लोकतंत्र की पुनर्स्थापना' के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। यह अपील परोक्ष रूप से विदेशी ताकतों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आमंत्रण देने जैसी है।

दूसरी ओर जब एक जिम्मेदार राष्ट्रीय नेता विदेशी धरती पर जाकर अपनी ही संवैधानिक संस्थाओं को 'कमजोर' बताता है, तो वह उन वैश्विक ताकतों का हौसला बढ़ाता है, जो भारत की मजबूत वैश्विक छवि और आर्थिक प्रगति से ईर्ष्या करती हैं। वस्तुतः इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक मोड़ तब देखने में आता है जब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क जैसे विदेशी कारोबारी भारतीय संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए लाइसेंस चाहती है किंतु भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामक पैमानों पर किसी भी प्रकार का समझौता करने से साफ इनकार कर दिया।

मस्क ने अपनी इस व्यावसायिक खीझ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर भारतीय नीतियों और स्वदेशी उद्यमियों (जैसे मुकेश अंबानी) के खिलाफ विषवमन करके निकाला। मस्क का यह चरित्र ही रहा है कि वे अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी देश के लोकतंत्र को मटियामेट करने की दंभपूर्ण सोच रखते हैं, जैसा कि बोलीविया के लीथियम भंडार पर कब्जा करने के लिए वहां के निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ रचे गए तख्तापलट की साजिश में उनकी स्वीकारोक्ति ('हम जिसका चाहें तख्तापलट करेंगे') से सामने भी आ चुका है।

सबसे बड़ा इसमें दुखद पहलू यह है कि राहुल गांधी इस मामले में भारत सरकार की सुरक्षा नीतियों के साथ खड़े होने के बजाय मस्क की भारत-विरोधी भावनाओं के साथ सुर मिलाते और उन्हें उकसाते नजर आए। ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति का एक बड़ा विरोधाभास यह है कि वे देश के भीतर रोजगार, बुनियादी ढांचा और पूंजी का निर्माण करने वाले भारतीय उद्यमियों (अडानी-अंबानी) को दिन-रात लांछित करते हैं, पर वहीं एलन मस्क जैसे बदमिजाज और मर्यादाहीन

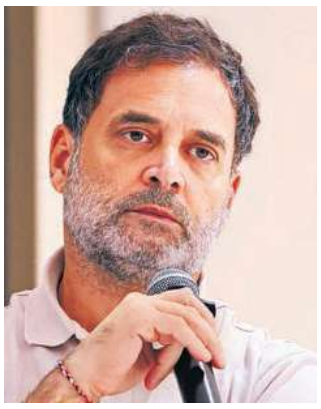



विदेशी उद्योगपति के आर्थिक स्वार्थों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। इससे पहले जब अमेरिकी राजनेता डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 'डेड इकोनॉमी' कहकर अपमानित करने का प्रयास किया, तब भी राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारतीय विकास दर के सकारात्मक और मजबूत अनुमानों को दरकिनार कर ट्रंप के दावों से सहमति जताने में देर नहीं लगाई। विदेशी कॉर्पोरेट्स के आगे इस प्रकार नतमस्तक होना और स्वदेशी उद्योगों की साख गिराना देश के आर्थिक स्वावलंबन पर सीधा प्रहार है। इसी तरह से लोकतंत्र की अंतिम रक्षा-पंक्ति उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, मगर अब उसे भी सड़क के हंगामे और राजनीतिक प्रदर्शनों के दबाव में लेने का एक खतरनाक चलन शुरू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन एक मामले के दौरान राहुल गांधी द्वारा मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा जताना और अनुमति न मिलने पर विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करना, कानून व्यवस्था का खुला मखौल उड़ाना नहीं तो क्या है? पुलिस-प्रशासन को चकमा देकर याचिका सौंपने के इस नए तरीके ने आंदोलनों की प्रकृति को पूरी तरह विकृत कर दिया है।

अब यह कोई संयोग नहीं है कि जब देश के भीतर अराजकता और आंदोलनों के जरिए मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास तेज होता है, ठीक उसी समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जैसी वैश्विक संस्थाएं भारत को लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्ञान देना शुरू कर देती हैं। इस एजेंसी के दोहरे रवैये की जितनी आलोचना की जाए, वह कम है। जब भारत के पड़ोसियों, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का खुलेआम कत्लेआम होता है, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और चुनी हुई सरकारों का हिंसक तख्तापलट होता है, तब ये वैश्विक पदाधिकारी मौन साध लेते हैं परंतु भारत में संसद द्वारा पास किए गए कानूनों या न्यायिक प्रक्रियाओं पर ये तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं! इससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए देश के भीतर की कुंठित राजनीतिक ताकतों और देश के बाहर बैठे पश्चिमी स्वार्थों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं व मस्क जैसे विदेशी अरबपतियों के बीच एक साठगांठ मजबूत होती जा रही है। घरेलू स्तर पर वैचारिक मतभेद कितने भी गहरे क्यों न हों, जब बात देश की संप्रभुता और सम्मान की आती है, तो किसी भी बाहरी शक्ति को जज बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कम से कम इतना तो राहुल गांधी जैसे विपक्ष के मुख्य नेता को समझना चाहिए।

वस्तुतः राहुल गांधी और उनके सहयोगियों को इस मामले में दक्षिण के राजनेता कमल हासन के उन देशभक्तिपूर्ण शब्दों से सीख लेनी चाहिए कि 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई उपनिवेश नहीं। हमारे यहां दुनिया का स्वागत है परंतु अपने भविष्य का फैसला भारत की जनता करेगी, पश्चिमी स्वार्थ या कोई विदेशी अरबपति नहीं।' ऐसे में कहना यही है कि देश की जनता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही इस टूलकिट और साजिश को भली-भांति समझ रही है और वह अपने लोकतंत्र की रक्षा विदेशी बैसाखियों के बिना, स्वयं करने में पूरी तरह सक्षम है। राहुल गांधी विचार करें, वे इस अराजकता से आखिर क्या प्राप्त कर लेंगे।

- (ये लेखक के निजी विचार हैं)

एआई का आतंकी चेहरा, सुरक्षा को लेकर नई चुनौती



डॉ. अनिल कुमार निगम
स्वतंत्र टिप्पणीकार

एआई का खतरा केवल हथियारों के स्वचालन तक सीमित नहीं है, यह झूठ को सच जैसा दिखाने, नफरत फैलाने और समाज के विश्वास को कमजोर करने की क्षमता भी रखता है। आतंकवाद हथियारों, विस्फोटकों, गुप्त नेटवर्क व मानव संसाधन पर निर्भर रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आतंकवादी संगठनों को प्रचार और भर्ती के नए रास्ते दिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब केवल विकास और नवाचार का औजार नहीं रहा, उसका दुरुपयोग आतंकवाद की पहुंच, प्रचार और प्रभाव को बढ़ाने का माध्यम भी बन सकता है। जिस तकनीक से दुनिया ज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा और रक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही है, वही तकनीक आतंकवादी संगठनों के हाथों में पड़कर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। सवाल यह नहीं कि एआई उपयोगी है या खतरनाक बल्कि यह है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए दुनिया कितनी तैयार है।

ब्रिटेन की घरेलू खुफिया एजेंसी एमआई-5 के प्रमुख सर केन मैक्कलम ने हाल ही में 2026 में एआई के दुरुपयोग से जुड़े आतंकवादी खतरों पर चिंता जताई है। यह चेतावनी भारत सहित उन सभी देशों के लिए प्रासंगिक है, जहां आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और डिजिटल दुष्प्रचार राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एआई का खतरा केवल हथियारों के स्वचालन तक सीमित नहीं है, यह झूठ को सच जैसा दिखाने, नफरत फैलाने और समाज के विश्वास को कमजोर करने की क्षमता भी रखती है।

परंपरागत आतंकवाद हथियारों, विस्फोटकों, गुप्त नेटवर्क और प्रशिक्षित मानव संसाधन पर निर्भर रहा है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आतंकवादी संगठनों को प्रचार और भर्ती के नए रास्ते दिए। अब जनरेटिव एआई इस डिजिटल तंत्र को अधिक तेज और व्यापक बना सकती है। बहुभाषी प्रचार सामग्री तैयार करना, नकली आवाजें और वीडियो बनाना तथा अलग-अलग समुदायों को लक्षित करने वाले संदेश तैयार करना पहले की तुलना में आसान हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरक्षेत्रीय अपराध एवं न्याय अनुसंधान संस्थान (यूएनआईसीआरआई) और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-रोधी केंद्र (यूएनसीसीटी) की रिपोर्ट ने एआई के इसी दोहरे उपयोग के प्रति आगाह किया है। तकनीक की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसका वैध इस्तेमाल करने वाले और उसका दुरुपयोग करने वाले, दोनों, समान डिजिटल साधनों तक पहुंच बना सकते हैं। इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ने सोशल मीडिया, वीडियो और ऑनलाइन नेटवर्क के जरिए अपने प्रचार तथा भर्ती को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया। उसका डिजिटल प्रचार एआई के व्यापक प्रसार से पहले शुरू हुआ था लेकिन आज एआई आधारित अनुवाद और सामग्री निर्माण जैसी क्षमताएं ऐसी रणनीतियों को अधिक भाषाओं और समुदायों तक पहुंचाने में मदद कर सकती हैं। यह अंतर समझना जरूरी है कि आईएसआईएस का पुराना डिजिटल प्रचार एआई के इस्तेमाल का प्रमाण नहीं, बल्कि उस डिजिटल पारिस्थितिकी का उदाहरण है, जिसे एआई और अधिक प्रभावी बना सकती है। अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय



(सीटीईडी) ने आतंकवाद और आतंकवाद-रोधी प्रयासों के संदर्भ में एआई के जोखिमों तथा अवसरों पर विशेषज्ञ चर्चा की थी। इस पहल ने स्पष्ट किया कि एआई का दुरुपयोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए संभावित खतरा है। एआई के खुले मॉडलों और उनकी सुरक्षा पर होने वाले शोध से भी चिंता बढ़ी है। यदि सुरक्षा प्रतिबंधों को दरकिनार कर हानिकारक सामग्री तैयार की जाती है तो तकनीक का दुरुपयोग बढ़ सकता है। भारत के संदर्भ में एआई और आतंकवाद का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। देश की विशाल डिजिटल आबादी, सीमापार आतंकवाद की चुनौती और सामाजिक विविधता ऐसी परिस्थितियां पैदा करती हैं, जिनमें डिजिटल दुष्प्रचार के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पहला खतरा, डीपफेक और सामाजिक अस्थिरता है। किसी नेता, सैन्य अधिकारी या धार्मिक व्यक्तित्व की नकली आवाज अथवा वीडियो को वास्तविक बताकर प्रसारित किया जाए तो इससे भ्रम, तनाव और अविश्वास पैदा हो सकता है। संवेदनशील घटनाओं के दौरान ऐसी सामग्री कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरा खतरा, सीमापार आतंकवाद का डिजिटल विस्तार है। एआई की मदद से बहुभाषी प्रचार और भ्रामक संदेश तैयार करना आसान हो सकता है। इससे आतंकवादी विचारधारा का प्रसार, युवाओं को प्रभावित करने के प्रयास और ऑनलाइन कट्टरपंथ की समस्या अधिक जटिल हो सकती है।

तीसरा खतरा, ड्रोन और साइबर सुरक्षा है। एआई सक्षम ड्रोन तथा स्वचालित तकनीकों का दुरुपयोग सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इसी तरह बिजली, संचार, परिवहन और बैंकिंग जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले व्यापक व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। चौथा खतरा, सूचना पर विश्वास का संकट है। जब नकली वीडियो और कृत्रिम आवाजें असली जैसी दिखाई-सुनाई देने लगें तो नागरिकों के लिए सही और गलत में अंतर करना कठिन हो सकता है। आतंकवादियों के लिए यह स्थिति भय फैलाने और संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने का अवसर बन सकती है।

भारत को एआई के संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए केवल प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। साइबर सुरक्षा, ड्रोन पहचान, डिजिटल फॉरेंसिक और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के विश्लेषण की क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है। एआई आधारित प्रणालियां सुरक्षा एजेंसियों को उपयोगी संकेत दे सकती हैं लेकिन अंतिम निर्णय में मानवीय जांच और कानूनी प्रक्रिया की भूमिका अनिवार्य होनी चाहिए। डीपफेक और फर्जी खबरों के विरुद्ध त्वरित तथ्य-जांच व्यवस्था विकसित करनी होगी।

- (ये लेखक के निजी विचार हैं)

विरोध... पुलिसकर्मियों से भिड़ंत, पेरिस में 1800 लोग गिरफ्तार
सरकारी इमारतों को बनाया निशाना, दुकानों में लूटपाट की

महंगाई के खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन

पेरिस • एजेंसी

फ्रांस में बढ़ती महंगाई और स्कूलों की खराब हालत के खिलाफ शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। राजधानी पेरिस में पुलिस ने 1800 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान हिंसक समूहों ने पुलिसकर्मियों से भिड़ंत की और दुकानों में लूटपाट की। प्रदर्शन में पेरिस क्षेत्र में करीब 1.10 लाख लोग शामिल हुए थे। देश के कई अन्य शहरों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं।

फ्रांस में शनिवार को हुए प्रदर्शनों में शामिल लोगों की संख्या को लेकर अधिकारियों और आयोजकों के आंकड़े अलग-अलग हैं। अधिकारियों के मुताबिक, देशभर में करीब 5.50 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया, जबकि आयोजकों ने यह संख्या लगभग आठ लाख बताई। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती जीवन-यापन लागत और स्कूलों में खराब सुविधाओं के खिलाफ नाराजगी जताई। हालांकि, कई जगह प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने से हालात बिगड़ गए।

सड़कों पर टूटे शीशे और बिखरे पत्थर

पेरिस के प्लास द ला रिपब्लिक इलाके में रविवार सुबह हिंसा के निशान दिखाई दिए। दुकानों के टूटे शीशे, सड़कों पर बिखरे कांच और उखड़े हुए पत्थर तोड़फोड़ की तस्वीर बयां कर रहे थे। शहर के मध्य हिस्से में कुछ अन्य पर्यटन और खरीदारी वाले इलाकों में भी दुकानों में लूटपाट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आईं। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को मध्य पेरिस में कई सौ से लेकर एक हजार से अधिक लोगों ने बिना अनुमति मार्च निकाले। दोपहर बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे, जिनका मकसद विरोध प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि हंगामे का फायदा उठाकर दुकानों में चोरी और लूटपाट करना था।

हिंसा में एक व्यक्ति की मौत, 15 घायल

पेरिस पुलिस के बयान के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जानकारी नहीं दी। फ्रांसीसी मीडिया की खबरों के अनुसार, मार्च के दौरान सड़क पर एक प्रदर्शनकारी की तबीयत बिगड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक, हिंसा के दौरान 13 पुलिसकर्मी और जेंडरमेरी के जवान तथा दो दमकलकर्मी घायल हुए।



मार्सेई में सिटी हॉल तक पहुंचे प्रदर्शनकारी

दक्षिणी बंदरगाह शहर मार्सेई में कुछ प्रदर्शनकारी थोड़ी देर के लिए सिटी हॉल की लॉबी में घुस गए। वहां एक पुलिस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचाया गया। वहीं, लियोन में एक पर्यटन कार्यालय के अंदर आग लग गई। इन घटनाओं ने प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी। फ्रांस के मध्य हिस्से में स्थित लिमोज शहर में सिटी हॉल में आग लगा दी गई। आग से 19वीं सदी की इस इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और इसकी छत ढह गई। हाउते-विएन के प्रीफेक्ट मॉरिस बारात ने एलसीआई टेलीविजन को बताया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। रविवार तक आग पर काबू पा लिया गया था।

ट्रंप ने देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों का उड़ाया मजाक

वाशिंगटन • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में फैली हिंसा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह देश मानो क्रांतियों के लिए ही बना है। बढ़ती महंगाई को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, लूटपाट हुई और आगजनी की घटनाएं देखी गईं। फ्रांस के हालात पर मजाक करते हुए ट्रंप ने कहा कि चलो फ्रांस चलते है? यह एक बहुत प्यारी जगह है। वहां कोई दंगे नहीं होते, कोई क्रांति नहीं होती। वैसे, फ्रांस तो क्रांतियों के लिए एकदम बेहतरीन जगह मिलती है। यकीन ही नहीं होता, चलो फ्रांस चलते हैं और क्रांति में शामिल होते हैं।

बैकफुट पर जेडी वेंस

वीजा धारकों को बंधुआ कहने पर दी सफाई

वाशिंगटन • अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि एच-1बी वीजा पर काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को बंधुआ मजदूर कहना गलत था। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक और औपनिवेशिक विरासत की याद दिलाने वाले बताए जाने के बाद वेंस का यह स्पष्टीकरण सामने आया है। वेंस ने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना का निशाना एच-1बी कर्मचारी नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियां और मौजूद वीजा प्रणाली थी। टाउन हॉल के दौरान एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक द्वारा पूछे गए सवाल पर



जवाब देते हुए वेंस ने अपने शब्दों की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों के चुनाव में कोई कमी रही है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरी यह टिप्पणी एच-1बी वीजा धारकों की आलोचना नहीं थी। जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो यह उस कंपनी की आलोचना है जो कर्मचारियों को इस स्थिति में रखती है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति- वेंस का यह बयान भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दर्ज कराई गई कड़ी आपत्ति के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रकार की शब्दावली को अनुचित और आपत्तिजनक करार दिया था। भारत ने कहा था कि इस तरह के बयानों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में भारतीय पेशेवरों के अभूतपूर्व योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

ईरान के नए रक्षा मंत्री मेहरदाद अखलाघी ने दी चेतावनी

अमेरिका ने फिर हमला किया तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे

तेहरान • एजेंसी

ईरान के नवनियुक्त रक्षा मंत्री मेहरदाद अखलाघी ने संसद में विश्वास मत हासिल करने के तुरंत बाद अमेरिका और उसके मध्य पूर्वी सहयोगियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने रविवार को यह स्पष्ट किया कि यदि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करता है, तो अमेरिका और उसके सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।



ईरानी मीडिया के अनुसर, संसद इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली ने मेहरदाद अखलाघी को रक्षा और सशस्त्र बल लॉजिस्टिक्स मंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग निश्चित रहें, अमेरिका और उसके सहयोगी हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें और पूरे क्षेत्र को भारी नुकसान होगा।

अखलाघी की यह नियुक्ति अमेरिका-इजराइल के शुरुआती हवाई हमलों के लगभग आठ महीने बाद हुई है। वे अजीज नासिरजादेह का स्थान लेंगे, जिनकी 28 फरवरी को एक नेतृत्व परिसर पर हुए हमले में मौत हो गई थी। उसी हमले में पूर्व सर्वोच्च नता आयातुल्ला अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर भी मारे गए थे।



अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद मंदिर किया सील

इस्लामाबाद • पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत स्थित डेरा इस्माइल खान के रहीम बाजार में स्थित ऐतिहासिक 'राम लीला मंदिर' को स्थानीय प्रशासन ने ताला लगाकर पूरी तरह सील कर दिया है। मंदिर की ऐतिहासिक इमारत को ध्वस्त कर वहां कमर्शियल प्लाजा बनाने की कथित साजिश के सामने आने के बाद नागरिक समाज और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कड़े विरोध के बाद प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा है। एसीपी हामिद सिद्दीकी के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद मंदिर परिसर में जारी हर तरह के निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। मंदिर को ध्वस्त कर व्यापारिक परिसर में बदलने की कोशिशों की खबर मिलने के बाद से अल्पसंख्यकों में रोष था।

हमले में एक व्यक्ति की मौत, पांच घायल

रूस पर यूक्रेन ने दागे 1,015 ड्रोन, सेंट पीटर्सबर्ग में तेल ठिकानों पर लगी आग

मॉस्को • एजेंसी

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में रविवार को बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले हुए। यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में एक हजार से ज्यादा ड्रोन दागे। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में तेल निर्यात टर्मिनल और तेल डिपो में आग लग गई। स्थानीय गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव के मुताबिक, हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच लोग घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के रूसी तेल ठिकानों पर हमलों की आलोचना की है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने की बात कही थी।

रविवार को हुए हमलों में रूसी रिटेल कंपनी ओजोन के लॉजिस्टिक्स सेंटर और टेक कंपनी वीके के डाटा सेंटर को भी निशाना



बनाया गया। दोनों कंपनियों ने अपने ठिकानों पर हमले की पुष्टि की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस के 15 क्षेत्रों के साथ-साथ क्रीमिया प्रायद्वीप और काला सागर के ऊपर कुल 1,015 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा है, जिस पर रूस ने कब्जा कर रखा है। यह हमला यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक बताया गया है।

मिडटर्म चुनाव : उम्मीदवारों ने विज्ञापनों के प्रचार पर किए 1300 करोड़ रुपए खर्च

अमेरिका में चुनावी प्रचार का नया हथियार बना एआई

वाशिंगटन • एजेंसी

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव से पहले राजनीतिक प्रचार में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। उम्मीदवारों और राजनीतिक संगठनों ने एआई से बने विज्ञापनों के प्रचार पर करीब 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक विज्ञापन में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी और गवर्नर कैथी होकुल को महंगाई और अपराध का डर दूर करने वाली दवा बेचते दिखाया गया है।

एक दूसरे विज्ञापन में मिशिगन के डेमोक्रेटिक सीनेट उम्मीदवार डॉ. अब्दुल एल-सय्यद का एआई से बना वीडियो दिखाया गया। इसमें वे 'डेथ टू अमेरिका' और '9/11 हमले का जश्न मनाओ' लिखे कार्ड देखकर हंसते नजर आए। एआई से बनाए गए कुछ विज्ञापनों में राजनीतिक विरोधियों को ऐसे नेताओं के साथ दिखाया गया, जिनसे जुड़ने पर मतदाताओं के बीच विवाद हो सकता है। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज जैसे नेता शामिल हैं। ओक्लाहोमा में 'मेक ओक्लाहोमा ग्रेट अगेन' नाम के एक समूह ने डेमोक्रेटिक गवर्नर उम्मीदवार को हिलेरी क्लिंटन के साथ गले मिलते दिखाया। वीडियो में दोनों को हाथ पकड़े हुए दिखाया गया, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किनारे उदास खड़े नजर आए। स्क्रीन पर लिखा था, 'क्लिंटन का समर्थक, ट्रंप का विरोधी।'

एआई का इस्तेमाल चुनावी रैलियों में ज्यादा भीड़ दिखाने के लिए भी किया जा रहा है। वहीं, फ्लोरिडा के गवर्नर पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार जेम्स फिशबैक के एक विज्ञापन में उन्हें डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर और ईरान के नेताओं के साथ पार्टी करते दिखाया गया।



डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एआई के इस्तेमाल पर सतर्क

डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एआई के इस्तेमाल को लेकर रिपब्लिकन उम्मीदवारों से ज्यादा सतर्क हैं। इसकी एक वजह यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक इस तकनीक की ज्यादा आलोचना करते हैं और इस पर नियम बनाने की मांग करते हैं। वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रैविस एन. रिडआउट ने कहा कि एआई का इस्तेमाल करने से डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों और संगठनों की छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा ज्यादा है।

19 करोड़ में बनने वाले विज्ञापन एआई से 1 करोड़ में बन रहे

हॉलीवुड की विज्ञापन कंपनी स्ट्रैटेजिक परसेप्शन के संस्थापक फ्रेड एन. डेविसे मुताबिक, एआई विज्ञापन बनाने की लागत काफी कम कर रहा है। उन्होंने एक विज्ञापन का उदाहरण देते हुए बताया कि इसे पारंपरिक तरीके से बनाने पर करीब लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च होते। इसमें कलाकारों, कपड़ों की व्यवस्था, खाने-पीने और कैमरा-लाइटिंग के साथ पूरे दिन की शूटिंग की जरूरत पड़ती। लेकिन एआई की मदद से वही दृश्य तैयार करने पर खर्च करीब 1.8 करोड़ रुपए रह गया है।